



देश के आईटी कानूनों के खिलाफ

इलेक्ट्रॉनिक एंड इनफॉर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय की ओर से वॉट्सऐप को भेजे नोटिस में कहा गया है कि यह पॉलिसी देश के आईटी कानूनों के खिलाफ है और इसे स्थगित करने भर से यह नहीं साबित होता कि कंपनी इन कानूनों का सम्मान करती है।

ज्योति सिंह।।

आखिर केंद्र सरकार ने अपना रुख सख्त करते हुए सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप से साफ-साफ कह दिया कि उसे अपनी नई प्राइवैसी पॉलिसी वापस लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक एंड इनफॉर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय की ओर से वॉट्सऐप को भेजे नोटिस में कहा गया है कि यह पॉलिसी देश के आईटी कानूनों के खिलाफ है और इसे स्थगित करने भर से यह नहीं साबित होता कि कंपनी इन कानूनों का सम्मान करती है। काफी समय से वॉट्सऐप की नई प्राइवैसी पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस चल रही है। यूजर्स का एक बड़ा हिस्सा इस पर खुलकर एतराज जता रहा है। केंद्र सरकार ने पहले भी वॉट्सऐप को पत्र भेजकर

उसकी नई प्राइवैसी पॉलिसी पर सवाल उठाया था, लेकिन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ने उस पर खास ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ इतना किया कि यूजर्स के लिए इस प्राइवैसी पॉलिसी को स्वीकारने की समय सीमा 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी। जाहिर है, इससे जुड़े सारे सवाल जस के तस रहे और 15 मई की समयसीमा गुजरने के बाद फिर सिर उठाने लगे। इस बीच यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया। वहां दायर याचिका में अदालत से गुजारिश की गई कि वह केंद्र सरकार को इस मामले में सख्ती बरतने को कहे।

कोर्ट में वॉट्सऐप ने कहा कि 15 मई की समयसीमा के बाद भी तत्काल किसी

यूजर का अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपनी यूजर्स को नई प्राइवैसी पॉलिसी स्वीकारने के लिए मनावा जारी रखेगी। जाहिर है, वॉट्सऐप अपने रुख पर अड़ी हुई है। तत्काल यूजर एकाउंट डिलीट नहीं करने का भला क्या मतलब बनता है? सवाल तो उसकी नई पॉलिसी के औचित्य पर है। आम यूजर्स ने जब उसकी सेवा लेनी शुरू की, तब उसने ऐसी शर्तें नहीं लगाई थीं। अब अचानक अपनी शर्तें बदल दे, यूजर्स को कोई विकल्प न देते हुए सीधा-सीधा कहे कि आपको यह सेवा

लेनी हो तो लें वरना न लें, यह मार्केट में अपने दबदबे का बेजा इस्तेमाल नहीं तो और क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह कि यही कंपनी यूरोपीय देशों के अपने यूजर्स के साथ जो संवेदनशीलता दिखा रही है, उनकी आपत्तियों के प्रति जैसा सम्मानजनक रुख प्रदर्शित कर रही है, उतना भी भारतीय यूजर्स के लिए नहीं कर रही। आखिर इस तरह के दोहरे मानदंड को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? वॉट्सऐप या उस जैसी किसी भी कंपनी को यह मानने की छूट नहीं दी जा सकती कि भारत के नागरिकों की निजता का अधिकार दुनिया के किसी भी दूसरे देश के नागरिकों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है या यह कि उसे यह अख्तियार है वह चाहे तो यहां के कानूनों को महत्व दे और चाहे तो न दे।



वह दे, यूजर्स को कोई विकल्प न देते हुए सीधा-सीधा कहे कि आपको यह सेवा

परमेश्वर के समीप

अशोक वोहरा।
स्वाध्याय और सत्संग के बाद अध्यात्म का तीसरा चरण आता है। इस चरण में आपको परमेश्वर का आभास तो है लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती। आपके मन मष्तिष्क में परमेश्वर की एक धुंधली सी छवि बन जाती है। इस धुंधलेपन को दूर करने के लिए आप इधर-उधर भटकते हैं। यहां पर आपको आवश्यकता महसूस होने लगती है, एक ऐसे व्यक्ति की जो आपका हाथ पकड़ कर उस परमेश्वर के समीप ले जाए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे गुरु जो सभी शंकाओं का निवारण करने में सक्षम हैं, वह स्वयं आएं या हमें उन्हें ढूँढना होगा। तो सीधी सी बात यहां पर ये है कि प्यासे को कुंए के पास जाना होता है ना कि कुंआ प्यासे के पास आता है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को खोजना रेगिस्तान में पानी ढूँढने जैसा ही है। आप इस पृथ्वी रूपी रेगिस्तान में ज्ञानरूपी पानी के लिए भटकते रहते हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

ड्रोन की भूमिका

इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में भविष्य में जो संघर्ष होंगे, उनमें ड्रोन की भी भूमिका होगी। 2018 में चीन ने इस तकनीक में अपनी महारत को एक लाइट शो के दौरान दिखाया था। तब चाइनीज ड्रोन आकाश में एक खास आकार में उड़े थे। चीन करीब 20 देशों को ड्रोन का निर्यात कर रहा है। सेथ यह भी कहते हैं कि अभी ड्रोन को यहां-वहां बिना किसी योजना के तैनात किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो देश अपने सारे ऑपरेशंस को ड्रोन तकनीक के साथ जोड़ पाएगा, वह सैन्य अभियानों के लिहाज से फायदे में रहेगा। लेकिन इससे मानव समाज किस तरह के भविष्य की ओर बढ़ेगा, उसका अंदाजा तकनीक और विज्ञान की दुनिया के ईलॉन मस्क और स्टीफेन हॉकिंग जैसे लोगों के बयान से लगता है। इन लोगों ने एआई आधारित हथियारों को नियंत्रित करने की अपील की है। विद्रोहियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों को लगता है कि ड्रोन की मदद से उनका पलड़ा भारी हो सकता है। आइसिस, हिजबुल्ला और बोको हराम, इन सभी आतंकवादी संगठनों के पास ड्रोन हैं। यूक्रेन और फिलीपींस के विद्रोहियों के पास भी। सेथ आने वाले समय में एआई आधारित हथियारों की होड़ की ओर इशारा करते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि इसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं।

अमेरिका दुनिया की अकेली ड्रोन पावर नहीं है। यह सच है कि उसे इस तकनीक में दूसरों से बेहतर होने का अहंकार रहा है। उसने इसे दूसरे देशों को देने में बहुत दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है।

हथियारों की नई होड़

मनोज वर्मा।।

27 जून की सुबह पाकिस्तान की ओर से जम्मू में बेहद सुरक्षित माने जाने वाले भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। खबर तो यह भी आई कि दो और ड्रोन आए थे, जिन्हें खदेड़ दिया गया। शायद वे एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे इलाकों में ड्रोन का दिखना नई बात नहीं। खालिस्तानी चरमपंथियों ने 2019 से पंजाब और जम्मू-कश्मीर में विस्फोटक, हथियार और ड्रग्स गिराने के लिए कई तरह से इनका इस्तेमाल किया है।

ज्यादातर ऐसे ड्रोन सीमा के पास से उड़ाए गए और फिर लौट गए। इनमें से कुछ किसी गड़बड़ी के कारण खुद-ब-खुद भारतीय सीमा में गिर गए या इन्हें मार गिराया गया। 21 मई को ही बीएसएफ ने जम्मू के सांबा इलाके में सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में आधा किलोमीटर अंदर एक एके-47, एक पिस्टल और कुछ गोल-बारूद बरामद किया था। इसके बाद जून में कटुआ के पास एक ड्रोन को मार गिराया गया। यह भी हथियार गिराने आया था। इसके मलबे से जीपीएस और कुछ दूसरे उपकरण मिले, जिनसे संकेत मिला कि इसने पाकिस्तान से उड़ान भरी थी। पिछले कुछ साल में ड्रोन का दुनिया के



अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों में भी इस्तेमाल बढ़ा है। पिछले साल 3 जनवरी को एक अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासेम सुलेमानी के दस्ते पर 6,200 मील की दूरी से तीन मिसाइलें दागीं। अमेरिका के जिस ड्रोन से यह हमला किया गया, उसे रीपर कहते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन की टोह लेने के साथ उस पर हमला करने के लिए भी होता है। जनरल सुलेमानी पर इस हमले को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रियल टाइम में देखा था। यानी जब हमला हो रहा था तो कदम-कदम उसकी तस्वीरें वह वाइट हाउस में लाइव देख रहे थे। इस हमले की वहां मौजूद सैनिक कुछ इस अंदाज में कमेंट्री कर रहा था, 'अब उनकी जिंदगी सिर्फ एक मिनट की बची है सर। अब 30 सेकंड अब 8 सेकंड अब वे खत्म हो चुके हैं सर।' तय है कि भविष्य के युद्ध एक शकल अख्तियार कर रहे हैं, जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। सेथ जे फ्रैंजमैन ने अपनी नई किताब 'ड्रोन वार्स:

पायनियर्स, क्लिंग मैशीन्स, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) एंड द बैटल फॉर द फ्यूचर' में यह दावा किया है। सेथ लिखते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत 70 के दशक के मध्य से हुई और इस्त्राएल ने यह काम शुरू किया। इस्त्राएली ड्रोन अटैक के शुरुआती अभियान से जुड़े याएर डुबेस्टर कहते हैं, 'डल, डेंजरस और डर्टी' मिशन यानी नीरस, खतरनाक और अवैध अभियानों के लिए ड्रोन अच्छे रहते हैं। इस किताब में आधुनिक तकनीक को लेकर अमेरिकी सेना के उत्साह का भी जिक्र है, जो कभी उफान पर होता है तो कभी रुक जाता है। अफगानिस्तान और इराक में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर बराक ओबामा सरकार के कार्यकाल के दौरान। इसके बावजूद अमेरिका दुनिया की अकेली ड्रोन पावर नहीं है। यह सच है कि उसे इस तकनीक में दूसरों से बेहतर होने का अहंकार रहा है। उसने इसे दूसरे देशों को देने में बहुत दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। ऐसे में कई देशों ने खुद पहल करके यह तकनीक विकसित की है। आज करीब 100 देशों के पास ड्रोन हैं।

ड्रोन तकनीक की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई बार इसी वजह से ताकतवर देशों को झुकना पड़ा है। इनमें अमेरिका से लेकर रूस और सऊदी अरब तक शामिल हैं।

सूटिंग बटाल-5315				सूटिंग बटाल-5314 का हेल			
8				1	5		
2				1	8		
3	4			6	7		9
5				9			
9		2	3	4			7
		1					8
4	7	6		5			1
	6	7					4
5	3						2

अपना ब्लॉग

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मोहन। अब सवाल उठता है कि जम्मू में एयर फोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिये जो हमला किया गया, उसे कैसे रोका जा सकता है? जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक करके यह काम किया जा सकता है। हालांकि, अगर वे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से लैस हैं या उनका अपना ऑप्टिकल सिस्टम है तो उन्हें लेजर या मिसाइल या बंदूक से मार गिराना होगा। सीरिया में गृहयुद्ध के दौरान भी ड्रोन का दोनों ओर से इस्तेमाल हुआ, जहां असद सरकार की ओर से रूसी और विद्रोहियों की ओर से तुर्की के ड्रोन मैदान में उतरे। विद्रोहियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों को लगता है कि ड्रोन की मदद से उनका पलड़ा भारी हो सकता है। आइसिस, हिजबुल्ला और बोको हराम, इन सभी आतंकवादी संगठनों के पास ड्रोन हैं। यूक्रेन और फिलीपींस के विद्रोहियों के पास भी। इस्त्राएल के पास ड्रोन आधारित बचाव तंत्र भी है, जिसे ड्रोन डोम कहते हैं। इस मामले में वह दुनिया के दूसरों मुल्कों से आगे है।

